**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1328**

**सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)**

## युवाओं के रोज़गार की स्थिति

**1328. डॉ. धर्मवीर गांधी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या और संगठित क्षेत्र में सृजित होने वाली गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की संख्या के बीच के अंतर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान श्रम बल में नए शामिल होने वाले युवाओं की संख्या की तुलना में सरकार द्वारा सृजित किए गए रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सतत आर्थिक विकास के बावजूद उच्च युवा बेरोजगारी के संबंध में चिंताओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने, कौशल विकास को बढ़ाने और देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से नवीनीकरण किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2022 में 38.5% से बढ़कर 2025 में 41.4% हो गया है; 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर

(एलएफपीआर) 2022 में 43.2% से बढ़कर 2025 में 46.0% हो गई है और देश में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022 में 10.6% से घटकर 2025 में 9.9% हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और इसमें 27 उद्योगों के रोजगार संबंधी अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार वर्ष 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 की अवधि के बीच 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

रोज़गार मेले एक प्रमुख पहल है जिसे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शुरुआत से अब तक, देश भर में आयोजित किए गए 19 रोज़गार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से लैस करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो

देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। इस योजना के भाग 'क' के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है; तथा भाग 'ख' के तहत, 83,535 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2068.84 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****